इंडिया बनाम भारत या इंडिया जो भारत है ?

राम पुनियानी

पिछले नौ सालों से भाजपा हमारे देश पर शासन कर रही है। विपक्षी पार्टियों को धीरे-धीरे यह समझ में आया कि भाजपा सरकार न तो संविधान की मंशा के अनुरूप शासन कर रही है और ना ही उसकी रुचि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित समावेशी भारत के निर्माण में है। भाजपा सरकार ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों को कमज़ोर करने के लिए कर रही है। इसके अलावा, उसकी नीतियाँ सरकार के साथ सांठगाँठ कर अपना उल्लू सीधा करने वाले पूंजीपतियों को बढ़ावा देने वाली हैं। वह प्रजातान्त्रिक अधिकारों को भी कुचल रही है। उसकी राजनीति राममंदिर, लवजिहाद और अन्य अनेक किस्मों के जिहादों, गाय, गोमांस और पहचान से जुड़े मुद्दों के अलावा, हमारे एक पड़ोसी देश पर अति-राष्ट्रवादी कटु हमले करने पर केन्द्रित है। उसकी नीतियों से आम लोगों, और विशेषकर गरीब और कमज़ोर वर्गों, की परेशानियां बढ़ीं हैं। चाहे वह नोटबंदी हो, कुछ घंटो के नोटिस पर देशव्यापी कड़ा लॉकडाउन लगाने का निर्णय हो, बढ़ती हुई बेरोजगारी और महंगाई हो या दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों के दमन में बढ़ोत्तरी हो- इन सबसे आम लोगों को ढेर सारी परेशानियां भुगतनी पड़ रही हैं।

भाजपा इस देश की सबसे धनी पार्टी है। उसने इलेक्टोरल बॉंड्स के ज़रिये अकूत धन इकठ्ठा कर लिया है। पीएम केयर फण्ड भी पार्टी की तिजोरी भरने का साधन बन गया है। इसके अलावा, पार्टी को आरएसएस और उसके अनुषांगिक संगठनों केलाखो कार्यकर्ताओं के रूप में प्रचारकों की एक विशाल फ़ौज उपलब्ध है। ये सभी चुनाव के दौरान और वैसे भी भाजपा के लिए काम करते हैं।

इस पृष्ठभूमि में गैर-भाजपा पार्टियों ने 'इंडिया' (भारतीय राष्ट्रीय विकास और समावेशिता गठबंधन) का गठन किया है। इस गठबंधन को बैंगलोर में इन पार्टियों के दूसरे सम्मलेन में आकार दिया गया। बैंगलोर में 26 राजनैतिक दलों ने प्रजातंत्र और संविधान को बचाने और भाजपा, जिसका संगठन मतदान केंद्र से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक फैला हुआ है और जो एक बढ़िया मशीन की तरह काम करता है, से मुकाबला करने के लिए एक साथ मिल कर काम करने का निर्णय लिया है।

इस संगठन के ठोस स्वरुप लेने से भाजपा चौकन्ना और परेशान हो गयी। सबसे पहले उसने एनडीए (राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक गठबंधन) को डीप फ्रीज़र से बाहर निकाला। इसमें 38 पार्टियाँ शामिल हैं, जिनमें से कुछ को छोड़कर सभी अनजान हैं। एनडीए के सम्मलेन में जो बैनर लगाया गया था उसमें केवल शीर्ष नेता का चित्र था और बाकी पार्टियों के नेता उनके आगे दंडवत कर रहे थे।

विपक्षी गठबंधन को इंडिया का नाम देने का निर्णय सचमुच बेहतरीन था और इससे भाजपा और उसके साथी बहुत घबरा गए। उन्होंने विपक्षी पार्टियों को भला-बुरा कहने के अलावा यह भी कहा कि इस नाम का इस्तेमाल अनुचित है। उनके अनुसार इससे चुनाव में मतदाता भ्रमित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी एएनआई ने खबर दी है कि इस सिलसिले में दिल्ली के बाराखम्बा पुलिस थाने में एक शिकायत भी भाजपा नेताओं ने दर्ज करवाई है।

भाजपा नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा इस बहस को एक कदम और आगे ले गए। उनके अनुसार इंडिया और भारत शब्द दो अलग-अलग सभ्यताओं के प्रतीक हैं। अंग्रेजों ने हमारे देश को इंडिया का नाम दिया था और हमें इस औपनिवेशिक विरासत से स्वयं को मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे पुरखों ने 'भारत' के लिए संघर्ष किया था और हमें भारत के निर्माण के लिए काम करना चाहिए।

सरमा पर तीखा पलटवार करते हुए कांग्रेस के जयराम रमेश ने ट्वीट किया: "उनके (सरमा) गुरूजी, श्री मोदी ने पहले से चली आ रही योजनाओं को नए नाम दिए- स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया। उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 'टीम इंडिया' के रूप में काम करने को कहा। यहां तक कि उन्होंने 'वोट इंडिया' की अपील भी की। पर ज्योंही 26 पार्टियों ने अपने गठबंधन को इंडिया का नाम दिया, उन्हें दौरा आ गया और वे इंडिया शब्द के इस्तेमाल को 'औपनिवेशिक मानसिकता' का प्रतीक बताने लगे।"

प्रधानमंत्री इससे इतने परेशान हो गये कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल को 'बीजेपी फॉर इंडिया' से 'बीजेपी फॉर भारत' में बदल दिया। प्रधानमंत्री के सभ्यताओं और मूल्यों के टकराव की बात करते ही हिन्दुत्ववादी लेखकों में इस मुद्दे पर लिखने की होड़ मच गयी। जेएनयू की कुलपति शांतिश्री धुलिपुड़ी पंडित ने लिखा, "भारत को मात्र संविधान से बंधे एक राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करना उसके इतिहास, उसकी प्राचीन विरासत, संस्कृति और सभ्यता की उपेक्षा करना है।" इसी गुट के अन्य लेखक तर्क दे रहे हैं कि सभ्यतागत मूल्यों को भारतीय संविधान के मूल्यों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

भारतीय सभ्यता की इन लेखकों की व्याख्या संकीर्ण है और केवल हिन्दू धर्म की ब्राह्मणवादी परंपरा पर केन्द्रित है। वे भारतीय सभ्यता की हूण और यूनानी सभ्यता से अंत:क्रिया को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं और भारत में इस्लाम और ईसाई धर्म के आगमन को नीची निगाहों से देखते हुए उसे हमारी सभ्यता पर 'विदेशी आक्रमण' ठहरा रहे हैं। यह आख्यान, जवाहरलाल नेहरु की भारतीय सभ्यता की समझ से एकदम उलट है। नेहरु ने लिखा है, "भारत एक ऐसी स्लेट है जिस पर एक के बाद अनेकानेक परतों में नए-नए विचार लिखे गए परन्तु कोई भी नयी परत, पिछली परत को पूरी तरह छुपा या मिटा न सकी।"

हेमंत सरमा एंड कंपनी के लिए भारतीय संस्कृति का अर्थ है वह कथित गौरवशाली काल जब ब्राह्मणवादी मूल्यों का बोलबाला था। वे तो चार्वाक, बुद्ध, महावीर, सम्राट अशोक और भक्ति-सूफी संतों जैसे विशुद्ध भारतीयों की परंपरा को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। वे रोमिला थापर, इरफ़ान हबीब, रामशरण शर्मा और हरबंस मुखिया जैसे "वामपंथी" इतिहासकारों से नफरत करते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि में भारतीय सभ्यता का अर्थ है जाति और लिंग आधारित ऊंच नीच। इन मेधावी इतिहासविदों ने समाज के गहरे सच को उजागर किया। उन्हें केवल 'शासक के धर्म' से मतलब नहीं था। उन्होंने दलितों, महिलाओं और आदिवासियों सहित समाज के सभी वर्गों की बात की और भारतीय सभ्यता की असली विविधता को हमारे सामने रखा।

दरअसल, दक्षिणपंथी विचारधारा ही औपिनिवेशिक विरासत की असली वाहक है। वह इतिहास को उसी चश्मे से देखती है जिस चश्मे को हमारे औपनिवेशिक आकाओं ने हमें दिया था। हमारे विदेशी शासक समाज को धर्म के आधार पर बांटना चाहते थे और इसलिए उन्होंने सांप्रदायिक इतिहासलेखन को प्रोत्साहन दिया जो इतिहास को तत्कालीन राजा के चश्मे से देखता है। हेमंत सरमा जैसे लोग इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, इसमें उन्होंने उच्च जातियों और पितृसत्तात्मक व्यवस्था के मूल्यों को भी जोड़ लिया है और यही मिक्सचर बहिष्करण पर आधारित उनकी राजनीति का आधार है।

उनकी राह में मुख्य बाधा है भारत का संविधान। जैसे-जैसे भारतीय राष्ट्रवाद की ताकत और प्रभाव बढ़ने लगा, इन लोगों ने मनुस्मृति और उसके कानूनों का महिमामंडन शुरू कर दिया और वे मुसलमानों, ईसाईयों और साम्यवादियों को देश का 'आतंरिक शत्रु' बताने लगे। भारत के संविधान का विरोध उनकी राजनीति का हिस्सा रहा है जिसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति पूर्व आरएसएस सरसंघचालक के. सुदर्शन ने की थी। उन्होंने कहा था कि संविधान देश के लोगों के लिए किसी काम का नहीं है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि विपक्षी पार्टियों के इंडिया का विरोध, हमारी सभ्यता के समावेशी मूल्यों का विरोध है। भारत का संविधान भी देश की सभ्यता के विकास का नतीजा है। इंडिया का विरोध सेम्युएल हट्टिंगटन की सभ्यताओं के टकराव के सिद्धांत के अनुरूप है और संयुक्त राष्ट्रसंघ की उस रपट के खिलाफ है जो सभ्यताओं के गठजोड़ की बात करती है और जो नेहरु के ऊपर दिए गए उद्धरण से मेल खाती है। हम केवल उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया, हेमंत सरमा जैसे लोगों की विघटनकारी राजनीति पर भारी पड़ेगा।

सांप्रदायिकता, हिन्दुत्व और बीजेपी का चुनावी तरीका

अभीष के. बोस द्वारा राम पुनियानी का साक्षात्कार

अनुवाद - नूतन भाकल

अभीष बोस : आपने राम जन्मभूमि आंदोलन के समय और उसके बाद, उत्तर भारत में इस विषय पर अत्यंत विस्तृत अध्ययन किया है, विशेष रुप से दंगाग्रस्त स्थानों में। इन जगहों पर सांप्रदायिक स्थिति के बारे में फिलहाल आप का क्या आकलन है?

राम पुनियानी : जिन स्थानों पर सांप्रदायिक हिंसा हुई है, वहां बहुत ध्रुवीकरण हुआ है और धार्मिक समुदायों के बीच भौतिक और भावनात्मक दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। बहुसंख्यक समुदाय अपने मन में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति नफरत की गलत धारणा पाले हुए है और अल्पसंख्यक समुदाय के मन में मुख्य भावना डर और असुरक्षा की है। सामाजिक और धार्मिक स्तर पर खुशियां साझा करना, पूरी तरह से खत्म हो गया है। राष्ट्र और भाईचारे के मूलभूत मूल्यों को गहरा झटका लगा है। सांप्रदायिक हिंसा के ज्यादातर जख्म अब भी भरे नहीं हैं।

हिंसा के शिकार लोगों को न्याय और उनके पुनर्वासन में सरकार की असफलता इसमें मुख्य अवरोध रहा है। जिन स्थानों पर हिंसा हुई है, वहां शायद नजदीकी भविष्य में दुबारा हिंसा न हो क्योंकि इन स्थानों पर ध्रुवीकरण लगभग पूरा हो चुका है और हिंसा की जिम्मेदार सांप्रदायिक ताकतों को इन्हीं स्थानों पर दोबारा हिंसा करके आम तौर पर कुछ खास उपलब्ध नहीं होता है। परंतु समग्र रूप से देश में हिंसा को बढ़ाने के लिए आवश्यक उकसावे के कारण बहुत ज्यादा हैं और भड़काना बहुत आसान है। अल्पसंख्यकों के विरुद्ध नफरत, वर्तमान राजनीतिक विमर्श

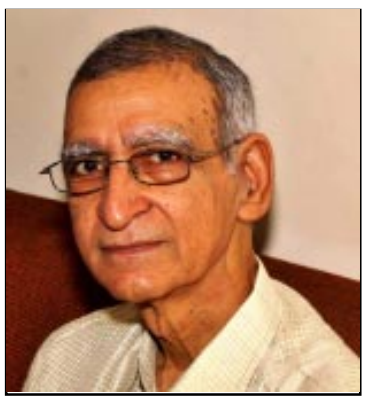

का एक मुख्य तत्व है।

अभीष बोस : विद्वानों ने यह माना है कि गुजरात दंगे भारतीय सांप्रदायिक हिंसा के लंबे इतिहास में विशिष्ट रूप से एक नए सांस्कृतिक आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सन 1984 के सिख दंगों के समान है, जिसमें लोगों को उसी तरह से निशाना बनाया गया था। क्या आप ऐसे वर्गीकरण की सैद्धांतिक और साक्ष्य आधारित उपयुक्तता की चर्चा करेंगे?

राम पुनियानी : सबसे पहले मैं यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सन 1984 के सिख-विरोधी दंगे और गुजरात दंगे तथा अन्य मुस्लिम-विरोधी दंगों की तुलना नहीं हो सकती है। धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा दो श्रेणियों में बांटी जा सकती है। एक, सिख-विरोधी हिंसा, जो कि एक अकेली घटना थी और अभागे सिख समुदाय के विरोध में राजनीतिक बदला लेने के लिए हुई। दूसरी, नियमित और बारंबार होने वाली हिंसा है, जो मुस्लिमों और ईसाइयों के विरुद्ध होती है और जो हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडा का एक हिस्सा है।

इन दोनों श्रेणियों में जो बात समान है, वह है, निरपराध लोगों के खिलाफ हिंसा का तरीका। यह हिंसा स्वत:स्फूर्त दिखाई देती है परंतु उसके पीछे योजना बनाई गई हो, ऐसा लगता है। नेतृत्व करने वाले लोग आम तौर पर इस हिंसा को ऐसे आयोजित करते हैं कि वह स्वत:स्फूर्त, ऊर्ध्वगामी दिखाई दे। यह ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया, अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ फैलाई गई नफ़रत के कारण पहले से ही तैयार की गई ज़मीन द्वारा उकसाई जाती है। सिख विरोधी नरसंहार, जो एक अकेली घटना थी, इंदिरा गांधी की हत्या का बदला लेने के लिए किया गया था, जो खालिस्तानी तत्वों द्वारा स्वर्ण मंदिर में बसने के बाद ऑपरेशन ब्लूस्टार की कार्रवाई का बदला लेने के लिए (इंदिरा गांधी की हत्या)की गई थी। गुजरात दंगे गोधरा ट्रेन की आग के बहाने आयोजित किए गए थे। मुसलमानों के घरों और दुकानों की सूची तैयार थी और उस शहर की तत्कालीन स्थानीय कलेक्टर जयंती रवि की सलाह के बावजूद, गोधरा में जले हुए मृतदेहों का जुलूस निकालकर लोगों को भड़काया गया। अल्पसंख्यक समुदाय पर 'उन्होंने आग लगाई' का आरोप लगाकर हिंसा की शुरुआत की गई ; स्थानीय लोग, विशेष रूप से निम्न लोग 'बदला' लेने के लिए बहकाए गए।

मुस्लिम-विरोधी हिंसा नियमित और बार-बार होती है; यह हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडा का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य समुदायों का ध्रुवीकरण कर चुनावी लाभ उठाना है। मेरा मानना है कि हिंसा को 'नीचे से' भड़का कर और उसमें भाग लेनेवालों को यह जता कर कि उन्हें दंडमुक्ति प्राप्त है, उसे आयोजित किया जाता है। हिंसा की उत्पत्ति का तरीका समान है, फिर भी उसके पीछे की राजनीति दोनों ही मामलों में बहुत अलग है।

अभीष बोस : इसका क्या कारण है कि निम्न वर्ग की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंदू राष्ट्रवाद की योजना और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है?

राम पुनियानी : भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति का चुनावी पक्ष है। इसके मूल संगठन ने दलितों और आदिवासियों के बीच कई अन्य संगठन बनाये हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी शाखाओं के विस्तृत नेटवर्क द्वारा स्वयंसेवकों की एक बड़ी फौज को प्रशिक्षित किया है, जो जमीनी स्तर पर और सामुदायिक स्तर पर समाज के इन तबकों के बीच काम करती है।

सबसे पहले वे धार्मिक दांव पेंच शुरू करते हुए, इन तबकों में हिंदू धार्मिक त्योहारों को बढ़ावा देते हैं । 70 और 80 के दशकों के बीच उनके स्वयंसेवकों ने भगवान गणेश के त्योहारों को दलित बस्तियों में बढ़ावा दिया। वे इस प्रकिया की शुरुआत करते, आर्थिक सहायता देते और दलित समुदायों को शामिल कर उनमें ब्राह्मणवादी मानदंड लागू करते।

आदिवासी क्षेत्रों में वे "शबरी संगम" आयोजित करते थे। शबरी रामायण में एक पात्र है, जो भगवान राम को बेर समर्पित करती है। वह गरीबी और अभाव का प्रतीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उसके नाम पर मंदिर बनाया है और उसे आदिवासियों की देवी के रूप में प्रस्तुत किया है। यह एक सांस्कृतिक संदेश भी है कि आदिवासियों का आदर्श कौन है।

इसके अलावा उन्होंने भगवान हनुमान को आदिवासियों के देवता के रूप में ढालना शुरू किया और आदिवासी बस्तियों में उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए कई अभियान शुरू किये। यह भी एक तरह से संदेश देने की बात है - राम के प्रति निष्ठावान, जिसे हिंदू राष्ट्रवादी ताकतों ने आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है। इससे धार्मिक स्तर पर इन तबकों को हिंदुवाद के आरएसएस संस्करण से जोड़ने में मदद मिली।

सामाजिक स्तर पर वे नियमित रूप से इन समुदायों के साथ नियमित रूप से मिलते-जुलते रहे, जिससे उन्हें सम्मान की भावना का एहसास हुआ। नियमित रूप से मिलते-जुलते रहने से इन समुदायों को सम्मानित होने का अहसास हुआ, जिसके परिणामस्वरूप चुनावी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई, जबकि भाजपा आरक्षण का विरोध करती है, आर्थिक आधार पर कोटा आरक्षण और जातिगत जनगणना का विरोध करती है। यह पूरी तरह से जमीनी स्तर पर इन समुदायों से मिलते-जुलते रहने के कारण हुआ,जो विस्तृत स्तर पर किया गया और जिसने चुनावी स्तर पर समाज के इन तबकों के बीच भाजपा के फायदे के लिए जमीन तैयार की।

अभीष बोस : एक परिप्रेक्ष्य के अनुसार 1980 के दशक के बाद भारत में "लोकतंत्र मजबूत" हुआ है। इसी दौर में एक प्रमुख ताकत के रूप में भाजपा भी उभर कर आई। भारत में लोकतंत्र का मजबूत होना और उसी समय भारत में भाजपा का उद्भव, इन दोनों को आप किस तरह से देखते हैं?

राम पुनियानी : यह सच है कि देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया गहरी होती जा रही है। यह प्रक्रिया समाज के निम्नतम वर्गों को अभिव्यक्त करती है। लोकतंत्र की मजबूती और सामाजिक परिदृश्य में दलितों और स्त्रियों के आगे बढ़ने से समाज के एक वर्ग को डर का एहसास हुआ और उसने सांप्रदायिक राजनीति का सहारा लिया।